

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील सं० 156/2017

स्वरूपसिंह पुत्र सांगसिंह
बनाम
खेतसिंह पुत्र सोहनसिंह वगैरा

दिनांक 27.11.2024

उक्त अपील राज० भू राजस्व अधि० 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं० 2286/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.5.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्प०-प्रार्थी-खेतसिंह, रेवन्तसिंह ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बाडमेर स्थित ग्राम सरणू भीमजी के ख०नं० 418/290, ख०नं० 420/290, ख०नं० 421/290 की कुल रकबा भूमि 242.10 बीघा किस्म गै०मु० ओरण भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलाट्स-अप्रार्थी सं० 16-स्वरूपसिंह ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलाट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी की भूमि ग्राम सरणू भीमजी के ख०नं० 289 रकबा 3.17 बीघा, खसरा नं० 290 के चिपते स्थित है। खसरा नं० 290 की भूमि के किनारे से सड़क निकल जाने के कारण इसका कुछ भाग सड़क से दूसरी तरफ चला गया व इस भाग पर रेस्प०-प्रार्थी व उसके रिश्तेदारों ने कब्जा किया हुआ है। जिसकी पूर्ति करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, ताकि इसकी आड़ में अपीलार्थी के ख०नं० 289 को ख०नं० 290 का भाग बताया जा सके। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया व तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में पक्षकारों को बिना सुने, पत्रावली केम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णय पारित कर दिया गया। रेस्प०-प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि स्वयं ग्राम पंचायत ने यह लिखकर दे दिया था, कि पूर्व में पत्थरगढी हो चुकी है व अब पत्थरगढी की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पैमाईश रिपोर्ट के बिना पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नहीं है। अतः अपील स्वीकार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

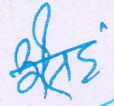
जवाब में रेस्प०-प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाट-अप्रार्थी सं० 16 को सुनवाई दिनांक 20.1.17 का नोटिस उसके पुत्र से तामिलशुदा मौजूद है। अपीलाट-विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रकरण

को मजमे आम में सुना गया। जिसमें रेस्पों-प्रार्थी एवं ग्रामीण जनता सरणू भीमजी, सरपंच ग्रा०पं० सरणू चिमनजी और सरपंच ग्रा०पं० सरणू पनजी ने दिनांक 12.5.17 को नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित सहमति/अनापत्ति व्यक्त की गई। अपीलाधीन खसरान की भूमि ग्राम पंचायत सरणू की गैर मुमकिन ओरण भूमि है तथा इसके पास में विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत स्थित है। विप्रार्थीगण व अन्य भूमाफिया गिरोह के व्यक्ति इस गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर बेचान करने से बचाव हेतु प्रार्थी एवं उपस्थित अन्य ग्रामीण जनहित में इसकी नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। जिस पर बाद सुनवाई व रिकॉर्ड अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई मजमे आम में की गई। जिसमें रेस्पों-प्रार्थी एवं ग्रामीण जनता तथा सरपंच ग्रा०पं० सरणू पनजी द्वारा नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित सहमति/अनापत्ति व्यक्त की गई तथा बाद सुनवाई एवं रिकॉर्ड अवलोकन अपीलाधीन आदेश द्वारा वादग्रस्त खसरान की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमेटी का गठन कर, ओरण भूमि की नेखमबंदी मजमे आम में करने हेतु निर्देशित किया है। जो राज्यहित में विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाट्स सारहीन पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 2286/2016 में पंजीयन अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।


27.11.24
(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर